

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम: एक शुरुआत

कनिका रॉय, समाजशास्त्र विभाग, ओ पी जे एस विश्विधालय, चूरू (राजस्थान)
डॉ अमित कुमार, समाजशास्त्र विभाग, ओ पी जे एस विश्विधालय, चूरू (राजस्थान)

प्रस्तावना

2013 में एनएफएसए की शुरुआत पीडीएस को मजबूत करने की दिशा में एक रचनात्मक कदम था। पारंपरिक कल्याण दृष्टिकोण से भोजन और पर्याप्त पोषण के मानव अधिकार की स्वीकृति पर आधारित दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हुए, एनएफएसए 800 मिलियन से अधिक लोगों या लगभग दो तिहाई लोगों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करने के लिए पीडीएस के उद्देश्य को औपचारिक रूप देता है। भारत की जनसंख्या. एनएसएफए की व्यापक प्रकृति ने कई मौजूदा खाद्य सुरक्षा उपायों को कानून में शामिल करने की अनुमति दी। एनएसएफए एक जीवन चक्र दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी, यह सभी आयु समूहों में आबादी की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करता है [81], और इसमें सभी भारतीयों के लिए उपलब्ध दोनों सार्वभौमिक पहलू शामिल हैं, जैसे कि मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत पीडीएस लक्ष्य को बरकरार रखते हुए बाल विकास सेवा योजना। एनएफएसए के तहत, 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, गेहूं और बाजरा (100 रुपये) पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह पाने की हकदार है। (रुपये) 1.39 USD के बराबर है।

पहले से मौजूद कई अधिकारों को औपचारिक बनाने के अलावा, एनएफएसए का लक्ष्य पीडीएस के समन्वय में राज्यों की भूमिका को मजबूत करना है, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है। एनएफएसए के प्रमुख उद्देश्यों में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के साथ, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर साझेदारी के माध्यम से भ्रष्टाचार, विचलन और रिसाव के मुद्दों के समाधान के लिए निगरानी उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है।

जबकि एनएफएसए में कृषि उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए "गेम चेंजर" बनने की पूरी क्षमता है, पोषण पर निरंतर प्रभाव डालने की एनएफएसए की क्षमता संदिग्ध है। जरूरतमंद परिवारों की पहचान करने में आने वाली समस्याओं का समाधान एनएसएफए द्वारा नहीं किया गया है, और अवैध कार्डों के साथ समस्याएं बनी हुई हैं [82]। अंत में, एनएफएसए से जुड़ी खाद्यान्न की बढ़ती आवश्यकता पर्यावरणीय स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इसके लिए उर्वरक, पानी और भूमि के उपयोग में वृद्धि की आवश्यकता होती है, जिस पर यदि ध्यान नहीं दिया गया, तो भूमि, वायु और जल प्रदूषण हो सकता है।

ट्रेकिंग और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस

यदि समर्थन और कार्यान्वयन किया जाए तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व बनने की क्षमता रखती है। सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटलीकरण के प्रसार के साथ, कम्प्यूटरीकरण से पीडीएस के संचालन में सुधार हो सकता है जिससे कुछ रिसाव कम हो सकता है। यह लाभार्थियों की पहचान में सहायता कर सकता है और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाते हुए लक्ष्यीकरण से जुड़ी समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों को कम कर सकता है। वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में परीक्षण की जा रही अन्य तकनीक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर नज़र रखने में वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम का अनुप्रयोग है। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करके काम करता है कि आपूर्ति श्रृंखला के सभी बिंदुओं पर सामान को अंदर और बाहर स्कैन किया जाता है, और अब तक भ्रष्टाचार, रिसाव और डायवर्जन में कमी देखी गई है और यह भी दिखाया है कि उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया सामान सिस्टम के कार्यान्वयन के बाद उच्चतर।

वैश्विक संदर्भ में भारत में खाद्य असुरक्षा

खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए अनेक उपाय अपनाने में भारत अकेला नहीं है। भारत की तरह चीन की भी बढ़ती अर्थव्यवस्था और बड़ी आबादी है। हाल के वर्षों में चीन में आर्थिक विकास के बावजूद, भारत की तरह, चीन भूखे लोगों की सबसे बड़ी आबादी में से एक है

[85]। जहां भारत खाद्य असुरक्षा को कम करने के लिए पीडीएस पर निर्भर है, वहीं चीन ने उन कार्यक्रमों पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया है जो धन का पुनर्वितरण और गैर-खाद्य आधारित सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं। चीन भी आहार पैटर्न में बदलाव का अनुभव कर रहा है, एक ऐसा बदलाव जिसका कृषि उत्पादन और भूमि के उपयोग पर प्रभाव पड़ रहा है [86]। इसी तरह, ब्राज़ील में कृषि क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा की स्थिति में बदलाव आ रहा है। चीन और भारत की आबादी की तरह, ब्राज़ील के लोगों के पास तेजी से वैश्विक आहार है, जो कृषि पैटर्न में बदलाव के लिए मजबूर कर रहा है। हालाँकि, इस परिवर्तन को बढ़ती खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए नकद हस्तांतरण और स्कूल भोजन कार्यक्रमों के साथ-साथ सरकार द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, प्रारंभिक संकेत कुछ सफलता का संकेत दे रहे हैं। इन देशों में ज़रूरतमंद बहुत बड़ी आबादी को देखते हुए, ऐसा कोई एक समाधान होने की संभावना नहीं है जो देशों के भीतर या सभी देशों में काम करेगा। आगे जो महत्वपूर्ण है, वह यह है कि इन कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने के लिए संपूर्ण और व्यापक डेटा एकत्र किया जाए।

सीमाएँ

अध्ययन किए गए साहित्य की कई सीमाओं को स्वीकार करने की आवश्यकता है। समीक्षा में शामिल 23 लेखों में भर्ती, डेटा संग्रह और विश्लेषण पर सीमित जानकारी तुलना को कठिन बनाती है और मेटा-विश्लेषण के किसी भी प्रयास को असंभव बनाती है। अधिकांश अध्ययनों में द्वितीयक डेटा का उपयोग परिणामों की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि यह पुराना या गलत हो सकता है, साथ ही माप त्रुटियों या पूर्वाग्रह के कारण कई अन्य नुकसान भी हो सकते हैं। हालाँकि लेखकों ने साहित्य समीक्षा करने के लिए एक व्यापक खोज रणनीति और कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, लेकिन अतिरिक्त लेख छूट गए होंगे। खाद्य सुरक्षा की बहु-क्षेत्रीय और बहु-आयामी प्रकृति सहित शोध विषय की जटिलता ने भी साहित्य समीक्षा पर सीमाएं लगा दी हैं। प्रासंगिक धूसर साहित्य, या जनता के लिए उपलब्ध न होने वाला साहित्य छूट जाने की भी संभावना है। अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रकाशन भी छूट गए होंगे।

पीडीएस पोषण और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिक्रिया देने वाली सरकारी नीति की आधारशिला है। हालाँकि, यह अक्षमताओं से भरा हुआ है जिससे ज़रूरतमंद लोगों को भोजन को प्रभावी ढंग से वितरित करने की इसकी क्षमता कम हो जाती है। एक सकारात्मक प्रतिक्रिया 2013 में एनएफएसए का कार्यान्वयन रही है, जिसने वैधानिक समर्थन प्रदान करके पीडीएस को मजबूत किया है। जैसा कि समीक्षा से पता चला है, पीडीएस और एनएफएसए की परिचालन क्षमता और स्थिरता पहलू में सुधार लाने के लिए लक्षित नीतिगत सुधार इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। पीडीएस भारत में कुपोषण और बचपन की रुग्णता या मृत्यु दर के मुद्दे को खत्म करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो यह भारत में भूख के स्तर को कम कर सकता है। पीडीएस को अन्य हस्तक्षेपों के साथ एकीकृत करने से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे अच्छे स्वास्थ्य का प्रचार करते हुए प्रत्येक नागरिक के पौष्टिक भोजन के अधिकार को साकार करने की क्षमता बढ़ सकती है।

यह समीक्षा भारत में खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने में पीडीएस की प्रभावशीलता की जांच करने वाली अपनी तरह की पहली समीक्षा है। अध्ययन में भारत में पीडीएस, एनएफएसए और खाद्य सुरक्षा के बारे में प्रकाशित शोध की कमी भी देखी गई। इससे मौजूदा हस्तक्षेपों के चूक जाने की संभावना बढ़ जाती है जिनमें भारत में खाद्य वितरण नेटवर्क में सुधार करने की क्षमता है। कुल मिलाकर, समीक्षा भारत में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अधिक समर्पित अनुसंधान की आवश्यकता को सामने लाती है जो सर्वोत्तम अभ्यास समाधानों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है जो पीडीएस की प्रभावकारिता और संचालन में सुधार करेगा।

द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में पीडीएस की शुरुआत की। यह बंबई (अब मुंबई के नाम से जाना जाता है) था जहां इसका पहली बार कामकाज शुरू हुआ था। धीरे-धीरे पहुंच का दायरा 13 अलग-अलग शहरों तक बढ़ गया और वर्ष 1946 तक पीडीएस प्रणाली और इसकी कार्यप्रणाली की पहुंच भारत के लगभग 771 शहरों तक पहुंच गई।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, वर्ष 1943 में अधिकांश देशों ने इस पीडीएस प्रणाली को बंद करने का निर्णय लिया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, भारत ने वर्ष 1950 में पीडीएस प्रणाली को फिर से शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, वैश्विक स्तर पर आसमान छूती कीमतों के कारण अनाज की कीमतें ऊंचाइयों पर पहुंच गईं। स्वतंत्रता के समय, भारत में अनाज (खाद्यान्न सहित) की आत्मनिर्भरता की कमी थी और उस समय वित्तीय तरलता की कमी और नकदी की कमी के कारण, देश के लिए जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज खरीदना संभव नहीं था। जन स्तर पर संपूर्ण भारतीय जनसंख्या का। इसलिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका ही था जिसने वर्ष 1956 में पीएल-480 अधिनियम के तहत भारत में पीडीएस प्रणाली की शुरुआत की थी। पीएल-480 अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विदेशी खाद्य सहायता के वितरण पर आधारित था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर (जिसे अब रूस के नाम से जाना जाता है) शीत युद्ध की स्थिति में थे। रणनीतिक और राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में दोनों देश अपने निहित स्वार्थों के लिए अपनी विभिन्न रणनीतिक जरूरतों के लिए उनका सहयोग लेने के लिए दूसरे देशों को उनके आर्थिक संकट से निपटने में मदद कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था की विचारधारा का समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर यूएसएसआर साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था के समर्थन में था। इसलिए दोनों देशों ने अपनी-अपनी विचारधाराओं का समर्थन किया।

साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था के अपने दृष्टिकोण को अपनी भौगोलिक सीमाओं से परे विस्तारित करने के यूएसएसआर के कदम को रोकने के परिणामस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1948 में मार्शल योजना पेश की जो वर्ष 1952 तक चली और इसका उद्देश्य पश्चिमी यूरोप को सहायता प्रदान करना था। ईआरपी (यूरोप रिकवरी प्लान) के तत्वावधान में युद्ध से तबाह देशों को गरीबी, विनाश, भूख जैसे युद्ध के बाद के परिणामों से निपटने में मदद करना और विभिन्न उपचारात्मक उपायों के माध्यम से ऐसे देशों को उनके पुनः आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में मदद करना है। यूरोप को लगभग 12 बिलियन की मौद्रिक सहायता दी गई और भोजन की कमी के संकट से लड़ने के लिए भारत को 31 मिलियन गेहूं और 0.19 मिलियन चावल प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई और उपरोक्त वस्तु के वितरण के लिए पीडीएस प्रणाली का होना आवश्यक था। यह व्यवस्था वर्ष 1960 तक जारी रही लेकिन दुर्भाग्य से 1962 में भारत-चीन युद्ध और 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण इसे अचानक बंद कर दिया गया।

1965 में, भारतीय खाद्य निगम (FCI) अस्तित्व में आया और वर्ष 1979 से PDS प्रणाली पूरी तरह कार्यात्मक हो गई है। पीडीएस ने खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि को रोकने में योगदान दिया था और इसने लाभार्थियों तक भोजन की पहुंच सुनिश्चित की थी और धीरे-धीरे हरित क्रांति के बाद राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ, पीडीएस की पहुंच दूर-दूर तक बढ़ गई थी। दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्र जहां 1970 और 1980 के दशक में गरीबी का स्तर काफी अधिक था और इस प्रणाली को पुनर्निर्मित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नाम दिया गया था। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आरपीडीएस) जून, 1992 में अस्तित्व में आई। इसका गठन पीडीएस संचालन को मजबूत और सुव्यवस्थित करने और दूर-दराज के क्षेत्रों तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लक्ष्य के साथ किया गया था, जो सूखे, अत्यधिक बर्फबारी के कारण दुर्गम हैं। और पहाड़ी, सुदूर या ज़मीन से घिरे हुए हैं। इस आरपीडीएस के तहत, दृष्टिकोण को व्यापक बनाया गया और विशिष्ट नामित पहाड़ी क्षेत्रों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी) जैसे कई अन्य कार्यक्रम चलाए गए, जिन्हें राज्य सरकारों के परामर्श से पहचाना गया था। विशेष विचार हेतु. ऐसे क्षेत्रों के लिए, राज्यों को सीआईपी (केंद्रीय निर्गम मूल्य) से 50 पैसे कम पर खाद्यान्न जारी किया जाता था और जारी मात्रा की सीमा 20 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड तक थी।

न केवल यहीं तक सीमित है बल्कि, आरपीडीएस में छूटे हुए परिवारों की मैपिंग और उन्हें राशन कार्ड जारी करना भी शामिल है। इसने बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के प्रक्षेपण में भी मदद की। अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानें, भंडारण क्षमता आदि और पीडीएस दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए दालें, चाय, नमक, साबुन आदि जैसी अन्य अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करना। जून 1997 में, भारत सरकार ने समाज के गरीब वर्ग पर विशेष ध्यान देने के साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) शुरू की। इस परियोजना के तहत, राज्यों को एफपीएस स्तर पर पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली में खाद्यान्न वितरण और वितरण के लिए समाज के गरीबी से जूझ रहे तबके की पहचान के लिए विभिन्न अचूक व्यवस्थाएं तैयार और कार्यान्वित करनी थीं और इस योजना का उद्देश्य लाभ पहुंचाना था। लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी से त्रस्त हैं।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बीपीएल) के लिए प्रारंभिक आवश्यक मात्रा से अधिक खाद्यान्न की मात्रा राज्य को "क्षणिक आवंटन" के रूप में दी गई थी, जिसके लिए सालाना 103 लाख टन खाद्यान्न आरक्षित किया गया था। टीपीडीएस आवंटन के अलावा, राज्यों को अतिरिक्त आवंटन भी आवंटित किया गया था। अस्थायी आवंटन का उद्देश्य एपीएल से ऊपर की आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का निरंतर लाभ देना था क्योंकि उनके लिए पीडीएस के तहत पहले से मौजूद लाभों को अचानक वापस लेना वांछनीय नहीं माना गया था। अस्थायी आवंटन पहले से ही रियायती दरों पर जारी किया गया था, लेकिन सब्सिडी मिलने के बाद भी, खाद्यान्न की दरें बीपीएल कोटा की कीमतों से अधिक थीं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्न के बढ़ते आवंटन और खाद्य सब्सिडी प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए खाद्यान्न का आवंटन 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह आर्थिक दर के आधे पर कर दिया है। 1-4-2000 से आर्थिक लागत पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को लागत और आवंटन। इसी तरह पीडीएस से भी छत्तीसगढ़ को काफी फायदा हो रहा है।

1. बुर्ची, एफ.; फैन्ज़ो, जे.; फ्रिसन, ई. छिपी हुई भूख से निपटने में भोजन और पोषण प्रणाली की भूमिका। इंटर. जे. पर्यावरण. रिस. सार्वजनिक स्वास्थ्य 2011, 8, 358-373।
2. गोडेके, टी.; स्टीन, ए.जे.; काइम, एम. दीर्घकालिक और छिपी हुई भूख का वैश्विक बोझ: रुझान और निर्धारक। ग्लोब. खाद्य सुरक्षा. 2018, 17, 21-29.
3. किशोर, ए.; चक्रवर्ती, एस. क्या अधिक समावेशी अधिक प्रभावी है? भारत में 'नई शैली' की सार्वजनिक वितरण प्रणाली। खाद्य नीति 2015, 55, 117-130।
4. सूरी, ए.; सामी, एन. द अर्बन। बेंगलोर, भारत की खाद्य प्रणाली; हंग्री सिटीज़ पार्टनरशिप: केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका, 2017।
5. बुकान, जे. भारत की खाद्य नीति विरोधाभास। अंडरकरंट 2007, 4, 1-7।
6. बनर्जी, ओ.; दरबास, टी.; ब्राउन, पी.आर.; रोथ, सी.एच. भारत और बांग्लादेश में खाद्यान्न प्रणालियों के सार्वजनिक प्रबंधन में ऐतिहासिक विचलन: खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के अवसर। ग्लोब. खाद्य सुरक्षा. 2014, 3, 159-166।
7. टैंकसेल, ए.; झा, जे.के. भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करना: मुद्दे और चुनौतियाँ। ब्र. फूड जे. 2015, 117, 1315-1335।
8. संधू, ए. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और भारत में खाद्य सुरक्षा परिणाम। विजन 2014, 18, 365-370।
9. रंगनाथ, वी. खाद्य सुरक्षा: मुद्दे और चिंताएँ। आईयूपी. लॉ रेव. 2015, 5, 7-13।